

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Saturday, 19 September 2026

कर्नाटक में डी.के. शिवकुमार ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार, नए और अनुभवी नेताओं को दी जिम्मेदारी

Sanket Morankar

Published on 03 Aug 2026



कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सोमवार को अपने मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार करते हुए शासन और संगठन दोनों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। मुख्यमंत्री **डी.के. शिवकुमार** के नेतृत्व में कैबिनेट में **20 नए मंत्रियों** को शामिल किया गया। इस विस्तार में पार्टी ने अनुभवी नेताओं के साथ-साथ नए चेहरों को भी अवसर देकर राजनीतिक और प्रशासनिक संतुलन साधने का प्रयास किया है।

राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल की उपस्थिति में नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। समारोह में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, विधायक और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पिछले कई दिनों से पार्टी के भीतर व्यापक चर्चा चल रही थी और अंततः केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बाद नई टीम को अंतिम रूप दिया गया।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने अपने मंत्रिमंडल के गठन में अनुभव और युवाओं के उत्साह के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है। कैबिनेट में ऐसे नेताओं को भी स्थान मिला है जिन्होंने लंबे समय तक संगठन और सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वहीं पहली बार मंत्री बनने वाले कई विधायकों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे कांग्रेस नेतृत्व ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि पार्टी वरिष्ठ नेताओं के अनुभव और नई पीढ़ी की ऊर्जा—दोनों को समान महत्व देती है।

इस विस्तार का एक प्रमुख उद्देश्य राज्य के विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना भी माना जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व ने उत्तर कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक, तटीय क्षेत्र और हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र सहित विभिन्न भौगोलिक हिस्सों से नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। इसके साथ ही विभिन्न सामाजिक समुदायों और वर्गों को भी प्रतिनिधित्व देकर व्यापक राजनीतिक संतुलन कायम रखने का प्रयास किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ कई दौर की चर्चा हुई। इन बैठकों में क्षेत्रीय समीकरण, संगठनात्मक योगदान, प्रशासनिक अनुभव और आगामी चुनावी रणनीति जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। इसके बाद मंत्रियों की अंतिम सूची को स्वीकृति प्रदान की गई।

इस विस्तार में कई ऐसे नेताओं को भी मंत्री बनाया गया है जो लंबे समय से संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे और मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहीं कुछ वरिष्ठ नेताओं को इस बार भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल सकी। इससे पार्टी के भीतर कुछ असंतोष की चर्चाएं भी सामने आई हैं। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि सभी निर्णय संगठन और सरकार के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखकर लिए गए हैं तथा भविष्य में भी योग्य नेताओं को अवसर मिलता रहेगा।

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य पारदर्शी, जवाबदेह और विकासोन्मुख प्रशासन देना है। उन्होंने नए मंत्रियों से अपेक्षा जताई कि वे जनता की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करें और सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करें। उन्होंने यह भी कहा कि सभी मंत्री टीम भावना के साथ कार्य करेंगे और सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी को निभाएं।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मंत्रिमंडल विस्तार केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस आगामी चुनावों से पहले संगठन को और मजबूत करना चाहती है। ऐसे में विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों को प्रतिनिधित्व देकर पार्टी ने अपने जनाधार को व्यापक बनाने की रणनीति अपनाई है। इससे सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने की उम्मीद भी जताई जा रही है।

विपक्षी दलों ने हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि केवल मंत्रिमंडल का विस्तार पर्याप्त नहीं है, बल्कि सरकार को रोजगार, कृषि, बुनियादी ढांचा, महंगाई और निवेश जैसे मुद्दों पर भी प्रभावी परिणाम देने होंगे। दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं का दावा है कि नई टीम के गठन से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और राज्य के विकास कार्यक्रमों को नई गति मिलेगी।

विशेषज्ञों के अनुसार, अब सबसे बड़ी चुनौती नए मंत्रियों के बीच विभागों का प्रभावी वितरण और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखना होगा। मुख्यमंत्री शिवकुमार से अपेक्षा की जा रही है कि वे प्रशासनिक दक्षता, जवाबदेही और विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए सरकार की कार्यशैली को अधिक प्रभावी बनाएं। इससे राज्य में निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक कल्याण योजनाओं और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की संभावना है।

कुल मिलाकर, कर्नाटक मंत्रिमंडल का यह विस्तार कांग्रेस सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक पड़ाव माना जा रहा है। नए और अनुभवी नेताओं के मिश्रण के साथ गठित यह टीम राज्य में सुशासन, समावेशी विकास और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार की नई रणनीति को दर्शाती है। आने वाले महीनों में मंत्रिमंडल का प्रदर्शन ही यह तय करेगा कि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर कितनी खरी उतरती है और विकास के अपने वादों को किस हद तक पूरा कर पाती है।